भाद्रपा (डी) विधिक प्रतिनिधि द्वारा

बनाम

तोलाचा नाइक

(2001 का सी.ए. सं. 7782)

8 जनवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी. सतशिवम, जे.जे.]

सरकारी अनुदान प्राप्त भूमि-हस्तांतरण/बिक्री सक्षम प्राधिकारी का आदेश कि अलगाव प्रभावित किया गया था निषेध की अवधि के भीतर-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। खरीदार द्वारा-आयोजित-का औचित्य न्यायोचित-स्थानांतरण था। अधिनियम में निहित निषेध का उल्लंघन करते हुए-यह साबित करने के लिए कि उसका कब्जा वैध था, बोझ व्यक्तिगत रूप से कब्जे में था जिसे वे स्थापित करने में विफल रहे-कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978-एसएस 4 (1), (2) और 5 (3)।

विचाराधीन भूमि एक प्रदत्त भूमि थी। अनुदान प्राप्तकर्ता जमीन बेच दी। इसे खरीदार द्वारा फिर से बेच दिया गया और अंत में बाद की बिक्री से, अपीलकर्ताओं ने भूमि खरीद ली। आवेदन के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई थी कि अनुदानकर्ता द्वारा अलगाव एस 4 द्वारा मारा गया था।

कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (का निषेध) कुछ भूमि हस्तांतरण) अधिनियम, 1978। एक आदेश पारित किया गया था एस 5 के तहत कार्यवाही में अधिनियम के इस प्रभाव के लिए कि निषेध की अवधि के भीतर अलगाव प्रभावित हुआ था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका और दायर रिट अपील को खारिज कर दिया अपीलार्थियों द्वारा। इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया गया कि:

कर्नाटक अनुसूचित जातियों की धारा 5 (3) और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के स्थानांतरण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 में प्रावधान है कि अनुदान प्राप्तकर्ता या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरण के तहत कब्जे में माना जाएगा। जो एस. एस. के तहत शून्य और शून्य है। 4 (1) और 4 (2) तक और जब तक कि कुछ भी विपरीत स्थापित न हो। बोझ, इसलिए, यह साबित करने के लिए कब्जे वाले व्यक्ति पर है कि उसका अधिकार कानून के अनुसार वैध था। यह था। तथ्यात्मक रूप से पाया गया कि रिट याचिकाकर्ता विफल रहा था एक ही स्थापित करें। स्थानांतरण का उल्लंघन था अधिनियम का निषेध। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय था रिट याचिका और रिट अपील को खारिज करने का अधिकार। [पैरा-8] [203-सी-ई]

गुन्टैया और ओआरएस बनाम हम्बम्मा और अन्य (2005) 6 एस.सी.सी. 228-संदर्भित।

सिविल न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7782/2001

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 09.11.2000 से, जो कि डब्ल्यू.ए.सं. 1886/2000 में पारित किया गया।

के साथ

सी.ए. संख्या 7799/2001

नरेश कौशिक, ललिता कौशिक, सतीश दया नंदन और जी.एस. पांडे - अपीलार्थियों के लिए।

एस.के. कुलकर्णी, जी. गिरीश कुमार और ख्वैरकपम नोबिन सिंह - प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि :

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

सिविल अपील सं. 7782/2001

1. पक्षकारों की सलाह सुनी गई।

2. इस अपील में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 4 (संक्षेप में 'उच्च न्यायालय अधिनियम') के तहत दायर रिट अपील को खारिज करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा

पारित आदेश को दी गई है। अपील में चुनौती एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई थी जिसने खारिज कर दिया था।अपीलार्थी-भद्रप्पा द्वारा दायर रिट याचिका। मृत्यु के बाद भद्रप्पा के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड में लाया गया और उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी हैं।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

विचाराधीन भूमि को वर्ष में कुछ समय दिया गया था। 1955 एक गोप्या नाइक के पक्ष में जिसे इसके बाद अनुदान प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है। सागुवली चिट 11.10.1956 पर जारी की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने वर्ष 1959 में एक के पक्ष में भूमि बेच दी। गंगप्पा ने उक्त भूमि को अहमद पाशा को बेच दिया और इसके बाद अहमद पाशा ने भद्रप्पा को बेच दिया। विचाराधीन भूमि पर सर्वेक्षण No.106 है जिसका माप 3 एकड़ और 5 गुंटा है।

4. के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई थी आवेदन कि अलगाव कर्नाटक की धारा 4 द्वारा प्रभावित हुआ था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (स्थानांतरण का निषेध) कुछ भूमि) अधिनियम, 1978 (संक्षेप में 'अधिनियम')।

5. अधिनियम की धारा 4 और 5 निम्नानुसार हैः

"4. प्रदत्त भूमि के हस्तांतरण का निषेध। -(1) किसी भी कानून, समझौते, अनुबंध में कुछ भी होने के बावजूद या लिखत, प्रदत्त भूमि का कोई हस्तांतरण या तो किया गया। द्वारा संप्रेषित किया जाए या कभी संप्रेषित किया गया समझा जाए इस तरह का स्थानांतरण।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद कोई भी व्यक्ति, बिना किसी अनुदानित भूमि के हस्तांतरण या अधिग्रहण सरकार की पूर्व अनुमति।

(3) उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान लागू होंगे।किसी डिक्री के निष्पादन में किसी भूमि की बिक्री के लिए भी या दीवानी अदालत या किसी अन्य के किसी पुरस्कार या आदेश का आदेश प्राधिकरण।"

5. प्रदत्त भूमि का पुनर्भुगतान और पुनर्स्थापन।-(1) जहाँ, किसी भी इच्छुक व्यक्ति या [2008] 1 एस. सी. आर. द्वारा आवेदन पर। किसी भी व्यक्ति या स्वतः संज्ञान द्वारा लिखित रूप में दी गई जानकारी,और ऐसी जांच के बाद जो वह आवश्यक समझता है,सहायक आयुक्त संतुष्ट हैं कि का स्थानांतरण धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत कोई भी प्रदत्त भूमि शून्य और शून्य है, वह

-

(क) बेदखल करने के बाद आदेश द्वारा ऐसी भूमि पर कब्जा कर लेना। उस पर अधिकार रखने वाले सभी व्यक्ति इस तरह से -निर्धारित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश इसके अलावा नहीं किया जाएगा प्रभावित व्यक्ति को उचित जवाब देने के बाद सुनने का अवसर;

(ख) ऐसी भूमि को मूल अनुदानकर्ता या उसके कानूनी रूप से पुनर्स्थापित करें। उत्तराधिकारी। जहां इसे बहाल करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है ऐसे अनुदानकर्ता या कानूनी उत्तराधिकारी को भूमि; ऐसी भूमि यह समझा जाए कि सभी बाधाओं से मुक्त होकर सरकार में निहित है। सरकार अनुदान दे सकती है किसी व्यक्ति को ऐसी भूमि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में भूमि अनुदान से संबंधित नियमों के अनुसार।

(1क) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जांच के बाद -सहायक आयुक्त, यदि वह संतुष्ट है कि किसी भी स्वीकृत भूमि का हस्तांतरण अमान्य नहीं है, तो एक आदेश पारित कर सकता है। तदनुसार]।

(2) उपायुक्त के आदेशों के अधीन धारा 5ए के तहत, उप-धारा (1) और (1ए) के तहत पारित कोई भी आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी भी मामले में सवाल नहीं उठाया जाएगा। कानून

की अदालत और किसी भी अदालत द्वारा की गई या की जाने वाली किसी भी कार्यवाही के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। सहायक आयुक्त द्वारा किसी भी शक्ति के अनुसरण में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई अनुदान दिया गया हो। भूमि एक व्यक्ति के कब्जे में है, अन्य तो मूल अनुदानकर्ता या उसका कानूनी उत्तराधिकारी, यह तब तक माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत यह साबित होता है कि ऐसे व्यक्ति ने एल. आर. एस. द्वारा भूमि बी. एच. ए. डी. आर. ए. पी. ए. (डी) का अधिग्रहण किया है। एक हस्तांतरण द्वारा जो के प्रावधानों के तहत शून्य और शून्य है धारा 4 की उप-धारा (1)"।

6. धारा के तहत कार्यवाही में एक आदेश पारित किया गया था 5 अधिनियम का इस प्रभाव के लिए कि अलगाव प्रभावित किया गया था प्रतिबंध की अवधि के भीतर। अपीलार्थी ने रुख अपनाया कि भूमि एक मुफ्त अनुदान भूमि नहीं थी। यह परेशान करने के लिए एक अनुदान था कीमत। अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक मुफ्त अनुदान था। रिट याचिका खारिज कर दी गई।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष स्थिति और डिवीजन बेंच को दोहराया गया।

8. अधिनियम की धारा 5 (3) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि कोई भी व्यक्ति अनुदान प्राप्तकर्ता या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के अलावा प्रदत्त भूमि, एक के तहत कब्जे में मानी जाएगी हस्तांतरण जो धारा 4(1) और 4(2) के तहत शून्य और शून्य है जब तक कि और जब तक कि कुछ भी विपरीत स्थापित नहीं किया जाता है। इसलिए बोझ,यह साबित करने के लिए कि उसका अधिकार कब्जे में व्यक्ति पर है कानून के अनुसार वैध था। यह तथ्यात्मक रूप से पाया गया कि रिट याचिकाकर्ता इसे स्थापित करने में विफल रहा था। गंगप्पा के पक्ष में स्थानांतरण प्रतिबंध का उल्लंघन था। एक्ट करें। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय ने खारिज करने में सही था रिट याचिका और रिट अपील। गुन्टैया और ओआरएस में। वी. हम्बम्मा और ओआरएस। (2005 (6) एस. सी. सी. 228 पैरा 14 पर) यह था निम्नलिखित रूप में नोट किया गयाः-

"अलगाव अनुदान प्राप्तकर्ता पर बाध्यकारी एक प्रतिबंधात्मक वाचा है। अनुदान प्राप्तकर्ता उस शर्त को चुनौती नहीं दे रहा है। इन सब में कार्यवाही, चुनौती तीसरे पक्ष द्वारा दी जाती है जो अनुदान प्राप्तकर्ता से भूमि खरीदी। तीसरा पक्ष नहीं है यह कहने का अधिकार है कि अनुदानकर्ता द्वारा लगाई गई शर्तें अनुदान प्राप्तकर्ता के लिए शून्य थे। जहाँ तक बिक्री अनुबंध की बात है और अनुदान प्राप्तकर्ता और उस समय तीसरे पक्ष का खरीदार इस तरह के लेन-देन में उनकी कोई रुचि नहीं थी। बेशक, वह

किसी भी वैधानिक उल्लंघन को चुनौती देने का अधिकार हो प्रावधान लेकिन यदि अनुदान स्वयं विशेष रूप से कहता है कि [2008] 1 एस. सी. आर. अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा एक अवधि के लिए कोई अलगाव नहीं होगा।15 वर्ष का, जो अनुदान प्राप्तकर्ता पर तब तक बाध्यकारी है जब तक वह उस खंड को चुनौती नहीं देता है, विशेष रूप से जब उसने खरीदा था भूमि, स्थिति से अवगत होने के बावजूद। पूरा पीठ ने यह ठहराते हुए गंभीर गलती की कि जमीन दी गई थी नियम 43-जे के तहत और यह कि अधिकारियों को अलगाव के संबंध में कोई शर्त लगाने का अधिकार नहीं था 1979 के अधिनियम 2 की धारा 4 को स्वीकार किए बिना। ये भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि लगभग मुफ्त में दी गई थी। और यह सुधार के लिए एक सामाजिक कल्याण उपाय के रूप में किया गया था गरीब भूमिहीन व्यक्तियों की स्थिति। जब ये जमीनें लाभ उठाते हुए तीसरे पक्ष द्वारा खरीदे गए थे इन भूमि को तीसरे से पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से पारित किया गया पार्टी खरीदार। जब 1979 के अधिनियम 2 को चुनौती दी गई थी,इस न्यायालय ने मानचेगौड़ा बनाम में टिप्पणी की। कर्नाटक राज्य (एससीसी पीपी। 310-11,पैरा 17)

17. अनुदानित भूमि लाभ के लिए थी और मूल अनुदान प्राप्तकर्ताओं का आनंद जो संबंधित हैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को। जिसमे अनुदान के समय के लिए एक शर्त लगाई गई थी प्रदत्त भूमि के हस्तांतरण को सीमित करके मूल अनुदान प्राप्तकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। इस तरह के हस्तांतरण पर निषेध के संबंध में शर्त एक निर्दिष्ट अवधि के लिए दी गई भूमि, द्वारा अधिरोपित की गई थी अनुदान में विशिष्ट अवधि के आधार पर या कारण से ऐसे अनुदान को नियंत्रित करने वाले किसी कानून, नियम या विनियम का। यह निस्संदेह अनुदान देने के समय अनुदानकर्ता के लिए खुला था। ऐसी शर्त निर्धारित करने के लिए मूल अनुदान प्राप्तकर्ताओं को भूमि शर्त स्वयं अनुदान की एक अवधि है, और अनुदान प्राप्तकर्ता के हित में शर्त लगाई गई थी। ऐसी शर्त के आधार पर अनुदानकर्ता ने ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया होगा। लगाई गई शर्त इस तरह की एक विशेष अवधि के लिए हस्तांतरण के खिलाफ भूमि जो अनिवार्य रूप से लाभ के लिए दी गई थी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को कोई अनुचित नहीं कहा जा सकता है प्रतिबंध। दी गई भूमि की प्रकृति की नहीं थी। के अर्थ के भीतर संपत्ति के अधिग्रहण या धारण का संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (च)। यह एक मामला था द्वारा प्रदत्त भूमि

का अधिकार और उपभोग अनुदान प्राप्तकर्ता और इस तरह के हस्तांतरण पर प्रतिबंध यह इंगित किया जाना चाहिए कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध नहीं था एक अनिश्चित अवधि या स्थायी के लिए। यह केवल एक के लिए था विशेष अवधि, उद्देश्य यह है कि अनुदान प्राप्तकर्ताओं को कम से कम इस अवधि के लिए स्वयं प्रदत्त भूमि का लाभ उठाएँ जिसके दौरान प्रतिबंध चालू रहना था। अनुभव से पता चला था कि संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनके लिए उनकी गरीबी के कारण, भूमि की कमी थी शिक्षा और सामान्य पिछड़ेपन, विभिन्न द्वारा शोषित ऐसे व्यक्ति जो दुख का लाभ उठा सकते थे और उठाएंगे इन गरीब व्यक्तियों की दुर्दशा उन्हें उनसे वंचित करने के लिए भूमि। पर प्रतिबंध की शर्त लागू करना इसलिए, किसी विशेष अवधि के लिए हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था किसी भी अनुचित प्रतिबंध का गठन माना जाता है प्रदत्त भूमि के निपटान के लिए अनुदान प्राप्तकर्ताओं का अधिकार। में निषेध पर ऐसी शर्त का अधिरोपण अनुदान की प्रकृति पूरी तरह से वैध और कानूनी थी।”

सिविल अपील संख्या-7799/2001:

9. संबद्ध में इंगित कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2001 की अपील No.7782 यह अपील बिना योग्यता के है।

10. पद होने के अलावा इनमें कोई योग्यता नहीं है। जिन्हें तदनुसार बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिद्धान्त शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।